महत्वपूर्ण एवं खास

निलंबित आइएएस रानू साहू की जमानत याचिका खारिज

रायपुर (आरएनएस)। निलंबित आइएएस रानू साहू की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं आईएएस समीर विश्नोई, सुनील अग्रवाल सहित अन्य को शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां इन सभी की न्यायिक रिमांड 23 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही कोल कंपनियों को नोटिस जारी करने के लिए ईडी को कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सुनील अग्रवाल की दो और सूर्यकांत तिवारी की एक कंपनी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि विशेष न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की कोर्ट में रानू साहू की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, जिस पर शनिवार को सुनवाई हुई। इससे पहले शुक्रवार को निलंबित आइएएस रानू साहू की 10 दिन की न्यायिक रिमांड पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया था। जिसके बाद फिर से न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया। शुक्रवार को कोर्ट का समय खत्म होने के कारण ईडी के वकील ने अपना पक्ष नहीं रख पाए थे जिसे शनिवार को ईडी का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।

मंदिर से लाखों के गहनों की चोरी

जांजगीर-चांपा (आरएनएस)। जांजगीर-चांपा जिले के बिर्रा थानाक्षेत्र में घिवरा गांव के डोकरी दाई मंदिर में चोरों ने 1 से 2 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवरात पार कर दिये। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार घिवरा गांव के डोकरी दाई मंदिर में शुक्रवार-शनिवार देर रात चोरों ने मंदिर के शटर में लगे ताले को तोड़ कर मंदिर के अंदर घुसे तथा माता की प्रतिमा के लगे गहने को चोरी कर ले गया। सुबह 6 बजे जब पुजारी मंदिर में आरती करने पहुंचा तब चोरी का पता चला। मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में आरोपी चोरी करते दिख रहा है। जिसमें अपने चेहरे को गमछे से छुपाये हुए एक व्यक्ति 1 बजकर 42 मिनट पर सबसे पहले मंदिर में घुसकर हाथ जोड़ता है तथा नीचे झुककर माता की प्रतिमा को प्रणाम करता है और प्रतिमा में लगे हार और सोने-चांदी के बाकी जेवरात निकालता है और फरार हो जाता है। चेहरे पर गमछा लपेटे होने से आरोपी की पहचान नही हो पाई है। मामले में पुजारी ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद बिर्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही डॉग स्कॉड की मदद से भी जांच-पड़ताल की जा रही है। मंदिर में चोरी की वारदात को गंभीरता से लेते हुए एसपी विजय अग्रवाल भी मौके पर पहुंचे। एसपी ने भी मंदिर परिसर का जायजा लिया और टीम को आरोपी को जल्द से जल्द पकडऩे के लिए निर्देशित किया।

कलेक्टर डॉ सिद्दीकी ने सारबिला कोचिंग के शिक्षकों और स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ली

सारंगढ़-बिलाईगढ़। कलेक्टर डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में निशुल्क सारबिला कोचिंग सारंगढ़, बरमकेला, भटगांव के शिक्षकों और स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ली। कलेक्टर ने कोचिंग के संचालन से जुड़े गतिविधियों के बारे में चर्चा की और शिक्षकों ने कलेक्टर को कोचिंग से जुड़े मांग, सुझाव की जानकारी दी। डॉ सिद्दीकी ने सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा अधिकारी डेजी रानी जांगड़े को निर्देश दिया। इस अवसर पर एसडीएम मोनिका वर्मा, डॉ स्निग्धा तिवारी, स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के नोडल अधिकारी चौहान, सारबिला कोचिंग के समन्वयक सत्येंद्र वसंत उपस्थित थे।

बारिश के बाद बाजार, मोहल्लों-कॉलोनियों से लेकर रिंग रोड तक बह गईं कई सड़कें

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में बुधवार और गुरुवार को करीब 36 घंटे की बारिश के कारण शहर की कई सडक़ें गड्ढों में तब्दील हो गयी हैं. बाजारों से लेकर कॉलोनियों और पुराने मोहल्लों के साथ-साथ रिंग रोड जैसी भारी ट्रैफिक वाली सडक़ों पर भी कहीं छोटे तो कहीं बड़े गड्ढे हो गए हैं। रिंग रोड के कुछ हिस्सों में गहरे गड्ढों में पानी भरने से सडक़ों की गहराई का पता नहीं चलता है। इससे यहां दुर्घटना का खतरा पैदा हो गया है। मोवा से सड्डू और सड्डू से सैंस सेंटर तक जाने वाली सडक़ बारिश में बेहद खराब हो गई है. वहां की सडक़ों पर गड्ढे होने के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कत हो रही थी. लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सडक़ का कार्य अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। इससे वहां के हजारों नागरिक परेशान हैं. मालवीय रोड और गोलबाजार की हालत सबसे खराब है, क्योंकि यहां पाइप लाइन बिछाने के साथ-साथ अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए बारिश के चरम मौसम में खुदाई की जा रही है। अभी लगातार बारिश के कारण गड्ढों की मिट्टी व गिट्टी बह गयी है, जिससे सडक़ पर चलना मुश्किल हो गया है।

पूरी गरिमा के साथ चक्रधर समारोह का 19 से 21 सितंबर तक होगा तीन दिवसीय आयोजन

- पंजरी प्लांट ऑडिटोरियम में होगा समारोह
- आयोजन समिति की बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय
- सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव होंगे नोडल
- राजा चक्रधर सिंह के पुत्र व पूर्व मंत्री स्व.भानुप्रताप सिंह के निधन के कारण विलंब से आयोजित हुई बैठक

रायगढ़। चक्रधर समारोह के आयोजन पर चर्चा के लिए कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आज बैठक आयोजित की गई। विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा, जिला पंचायत अध्यक्ष निराकार पटेल, महापौर जानकी काटजू, सभापति जयंत ठेठवार, विजय अग्रवाल, देवेन्द्र बहादुर सिंह, सुश्री उर्वशी देवी सहित शहर के गणमान्य नागरिक और अधिकारी शामिल हुए।

बैठक की शुरुआत में कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि विधानसभा सदस्य व कैबिनेट मंत्री रहे स्व.श्री भानूप्रताप सिंह के विगत 14 जून को निधन हो गया था। उनके परिवार के सदस्यों द्वारा शासन को समारोह स्थगन को लेकर पत्र लिखा गया था। जिसको देखते हुए यह बैठक पहले आयोजित नहीं की जा सकी थी। आज कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में समिति की बैठक की जा रही है। बैठक में उपस्थित समिति सदस्यों ने आयोजन की अवधि और कार्यक्रम स्थल को लेकर अपने विचार रखे। जिसके पश्चात आयोजन समिति द्वारा सर्वसम्मति से इस वर्ष चक्रधर समारोह का पूरी गरिमा के साथ त्रि-दिवसीय आयोजन नगर निगम ऑडिटोरियम में करने का निर्णय लिया गया। चक्रधर समारोह का आयोजन 19 सितंबर से 21 सितंबर तक किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजन के लिए सीईओ जिला पंचायत जितेन्दर यादव (भाप्रसे) नोडल अधिकारी होंगे। वहीं नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी सहायक नोडल होंगे।

बैठक में जगदीश मेहर, नटवर सिंघानिया, राजेश पटनायक, दिनेश जायसवाल, प्रताप खोडियार, देवेश शर्मा, दीपक पाण्डेय, रामचंद्र शर्मा, नरेश शर्मा, हरेराम तिवारी, युवराज सिंह आजाद, शेख ताजिम, महावीर अग्रवाल, कैलाश आचार्य, अनुपम पाल, अपर कलेक्टर सुश्री संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव पाण्डेय, एडिशनल एसपी संजय महादेवा, नगर निगम आयुक्त सुनील चंद्रवंशी, एसडीएम रायगढ़ गगन शर्मा, सीएसपी अभिनव उपाध्याय सहित समिति से जुड़े अन्य सदस्य व अधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ सरकार ने जूनियर डाक्टरों की शिष्यवृत्ति बढ़ाने का लिया निर्णय

- मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट कर दी जानकारी

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जूनियर डाक्टरों की शिष्यवृत्ति बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिसकी जानकारी उन्होने अपने ट्वीट के माध्यम से दी है। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि यह साझा करते हुए संतोष हो रहा कि हमने जूनियर डॉक्टर्स की शिष्यवृत्ति में वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की शिष्यवृत्ति में जो बढ़ोत्तरी की है। उसके नवीन दर के अनुसार पीजी प्रथम वर्ष के लिए 53 हजार 550 रूपये से बढ़ाकर 67 हजार 500 रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। इसी तरह पीजी द्वितीय वर्ष के लिए 56 हजार 700 रूपये से बढ़ाकर 71 हजार 450 रूपये प्रति माह तथा पीजी तृतीय वर्ष के लिए 59 हजार 200 रूपये से बढ़ाकर 74 हजार 600 रूपये प्रति माह करने का निर्णय लिया है। एम.बी.बी.एस. के इंटर्नशिप के छात्रों के लिए 12 हजार 600 रूपये से बढ़ाकर 15 हजार 900 रूपये प्रति माह किया गया है। इस प्रकार से राज्य सरकार के इस निर्णय से अब जूनियर डाक्टरों की शिष्यवृत्ति में साढ़े 3 हजार रूपये से लेकर 15 हजार रूपये तक की बढ़ोत्तरी होगी।

मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना... सत्यनारायण पटेल को मिला योजना का आर्थिक लाभ

महासमुंद (आरएनएस)। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के तहत विकासखण्ड महासमुंद के ग्राम जलकी निवासी श्रमिक सत्यनारायण पटेल के खाते में 20 हजार रुपए की राशि प्राप्त हो गई है। यह योजना छत्तीसगढ़ प्रदेश के श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरु की गई है। इस योजना के माध्यम से निर्माण श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। श्रम अधिकारी जी.के. पांडेय ने बताया कि जिले में इस योजना में 376 श्रमिक सियान पंजीकृत है। अब तक परीक्षण उपरांत 244 श्रमिक सियान को 20-20 हज़ार की एकमुश्त राशि प्रदाय की गई है। शेष श्रमिक सियान के दस्तावेजों का परीक्षण किया जा रहा है।

श्रमिक सत्यनारायण पटेल ने बताया कि वे खेती-मजदूरी का काम करते है। उन्होंने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना की जानकारी मिली और श्रम विभाग में इसका आवेदन किया। श्रम विभाग के सहयोग से सहायता राशि 20 हजार रुपए उनके बैंक खाते में आ चुका है। उन्होंने कहा कि 60 वर्ष की उम्र में निर्माण मजदूरी में शरीर भी ज्यादा मजदूरी करने अक्षम रहता है और लोग भी काम नहीं देते। राज्य शासन की यह योजना हम जैसे श्रमिकों के लिए वरदान बनी है और खाते में 20 हजार रुपए की राशि हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत उपयोगी है। इसके लिए उन्होंने शासन का आभार जताया और उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद कहा।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिकों को मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने से पहले बेहतर जीवन यापन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में 20,000 रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान की जा रही है। श्रमिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना होगा। अधिक राशि प्राप्त कर श्रमिक अपना जीवन यापन उच्च तरीके से कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें किसी अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर अब उपलब्ध होंगे छत्तीसगढ़ हर्बल के उत्पाद

- छत्तीसगढ़ के जंगलों की प्राकृतिक शुद्धता की पूरे देश में बिखरेगी छटा
- स्व-सहायता समूह की महिलाओं की समृद्धि के लिए तीन सरकारी संस्थाओं का एमओयू

रायपुर (आरएनएस)। यह छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक क्षण है, जब वनवासियों के सतत् विकास, आजीविका और महिला सशक्तिकरण की दिशा में तीन सरकारी संस्थान साथ आए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज सहकारी संघ, आईआईएम रायपुर और केंद्रीय भंडार ने छत्तीसगढ़ हर्बल्स को लेकर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस एमओयू के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को-ऑपरेटिव के सभी केंद्रीय भंडार स्टोर्स पर अब छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद उपलब्ध होंगे। प्रदेश की स्व-सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक विकास और समृद्ध भविष्य के लिए यह तीनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, इससे वनवासी ग्रामीण महिलाओं और वन संग्राहकों की मेहनत को अब देश भर में नई पहचान मिलेगी।

इस एमओयू का सबसे बड़ा लाभ वनवासी महिलाओं को मिलेगा, जो हर दिन कड़ी मेहनत, लगन और विश्वास से छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पाद बना रही हैं। इनके बनाए उत्पादों को राष्ट्र व्यापी बाजार सुलभता से उपलब्ध होगा। छत्तीसगढ़ हर्बल्स भारत का पहला लघु वनोपज आधारित ब्रांड बनने की दिशा में तेजी से विकसित हो रहा है। प्रदेश के जंगलों की प्राकृतिक शुद्धता अब पूरे देश में पहुंचेगी और राज्य की इन वनवासी महिलाओं को अतिरिक्त आमदनी होगी। वे स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ेगी।

आदिवासी महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा बनाए गए छत्तीसगढ़ हर्बल्स के उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आईआईएम रायपुर केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों को रिटेल मैनेजमेंट का प्रशिक्षण प्रदान करेगा। केन्द्रीय भंडार को आईआईएम रायपुर की प्रशिक्षण विशेषज्ञता से लाभ होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में राज्य में लघु वनोपजों के संग्रहण के साथ-साथ उनके प्रसंस्करण तथा विपणन आदि की सुगम व्यवस्था के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

एमओयू पर हस्ताक्षर के अवसर पर सीजीएमएफपी फेडरेशन के प्रबंध निदेशक अनिल राय ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है कि तीन बड़ी सरकारी संस्थाएं ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पाद छत्तीसगढ़ हर्बल्स की बिक्री के लिए सहयोग करेंगे। जिससे स्व-सहायता समूह की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी।

आईआईएम रायपुर के निदेशक डॉ. राम कुमार काकानी ने कहा कि आईआईएम रायपुर पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की आजीविका की समृद्धि में सहयोग करेगा। हमारे विशेषज्ञों की टीम केंद्रीय भंडार के कर्मचारियों और राज्य लघु वनोपज संघ के साथ मिलकर निरंतर बेहतर काम करने के लिए संकल्पित है।

जिले के नवीन स्वामी आत्मानंद स्कूल भवनों का कायाकल्प अंतिम चरण में

- कलेक्टर सिन्हा ने सीएसआर से 31 स्कूलों के लिए जारी किए हैं 15.72 करोड़
- क्लासरूम्स को कर रहे अपग्रेड, बच्चों को मिलेगा बेहतर माहौल
- निर्माण एजेंसियों को गुणवत्ता के साथ काम करने के कलेक्टर सिन्हा ने दिए हैं निर्देश

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मंशानुरूप प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने राज्य शासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के द्वारा निम्न व मध्यम आय वर्ग के बच्चों को बिना फीस के चिंता किए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में भी निरंतर कार्य हो रहा है।

जिसके तहत जिले में 31 स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ हुए हैं। इसके उन्नयन के लिए कलेक्टर सिन्हा ने सीएसआर मद से 15 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि स्वीकृत किए थे। इन स्कूल बिल्डिंग का कायाकल्प अपने अंतिम चरणों में हैं। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देश पर इन विद्यालयों का मरम्मत का कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा हैं। इसके साथ ही उन्नयन कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए इसके लिए उन्होंने सभी एसडीएम नियमित निरीक्षण के निर्देश भी दिए हुए हैं।

जिले के सभी 7 विकासखंडों में इस सत्र में 31 नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित हो रहे हैं। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा इन स्कूल भवनों के उन्नयन के लिए सीएसआर से स्वीकृत राशि से भवन के जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इन स्कूलों में भवन के मरम्मत के साथ रंगाई-पुताई का कार्य किया जा रहा है। लगभग 50 लाख रुपए की राशि एक स्कूल के लिए दी गई है। क्लासरूम के साथ ही स्कूल के शौचालय की मरम्मत की जा रही है। छत और फ्लोर को भी सुधारा जा रहा है। जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल और बेहतर संसाधन मिल सकें।

इन स्वामी आत्मानंद स्कूलों का हो रहा कायाकल्प

शास.उ.मा.विद्यालय महापल्ली, मुकुन्द देव गुप्ता शास.उ.मा.विद्यालय लोईंग, शास.उ.मा.विद्यालय पतरापाली, शास.उ.मा.विद्यालय टारपाली, शास.उ.मा. विद्यालय चक्रधर नगर रायगढ़, शास.उ.मा. विद्यालय नंदेली, शास.उ.मा.विद्यालय किरोड़ीमलनगर, शास.उ.मा.विद्यालय पडिगांव, शास.उ.मा.विद्यालय तेतला, शास.उ.मा.विद्यालय औरदा, शास.उ.मा. विद्यालय बड़े भंडार, शास.उ.मा.विद्यालय कन्या घरघोड़ा, शास.उ.मा.विद्यालय रायकेरा, शास.उ.मा.विद्यालय छर्राटांगर, शास.उ.मा.विद्यालय गोरपार, शास.उ.मा. विद्यालय मुरा, शास.उ.मा.विद्यालय मदनपुर, शास.उ.मा.विद्यालय चपले (अंग्रेजी माध्यम), शास.उ.मा.विद्यालय धौराभांठा, शास.उ.मा.विद्यालय तराईमाल, शास.उ.मा.विद्यालय कुंजेमुरा, शास.उ.मा. विद्यालय कन्या गोढ़ी, शास.उ.मा.विद्यालय हमीरपुर, शास.उ.मा.विद्यालय राजपुर, शास.उ.मा.विद्यालय बसंतपुर, शास.उ.मा. विद्यालय झगरपुर, शास.उ.मा.विद्यालय लारीपानी, शास.उ.मा.विद्यालय सिसरिंगा, शास.उ.मा.विद्यालय कटाईपाली-सी, शास.उ.मा.विद्यालय कापू एवं शास.उ.मा. विद्यालय हाटी शामिल है।

स्कूली छात्राओं ने खास सहेलियों को बांधी स्वीप फ्रेंडशिप डे का धागा

सारंगढ़-बिलाईगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान (स्वीप) के तहत शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सारंगढ़ के सभागार में स्कूली छात्राओं ने जिले में 6 अगस्त को मनाए जा रहे स्वीप फ्रेंडशिप डे का कार्यक्रम शनिवार को मनाया। जहां छात्राओं ने स्कूल में अपने खास सहेलियों को स्वीप फ्रेंडशिप डे का धागा बांधी। इस धागा के माध्यम से अपने दोस्तों, परिवार और दैनिक दिनचर्या से जुड़े सभी लोगों को जानकारी देकर जन जन तक मतदान के लिए जागरूकता का प्रसार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को जारी की 15.29 करोड़ रूपए की राशि

- हितग्राहियों को अब तक हो चुका है 541.66 करोड़ का भुगतान
- गोधन न्याय योजना को सिर्फ छत्तीसगढ़ नही बल्कि देश भर में मिल रही सराहना : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 73वीं किश्त के रूप में 15 करोड़ 29 लाख रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर 14-31 जुलाई 2023 तक गौठानों में गोबर विक्रय करने वाले ग्रामीण पशुपालक किसानों को 5 करोड़ 60 लाख रूपए तथा गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 9 करोड़ 69 लाख रूपए की राशि जारी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत तीन वर्षों में गोधन न्याय योजना ने अद्वितीय सफलताएं हासिल की है। इस योजना को न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश भर में सराहा गया है। देश के अनेक राज्यों ने हमारा अनुशरण करके इस तरह की योजना लागू की हैं। इस योजना के माध्यम से स्व-सहायता समूह की बहनें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनी है। गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों ने अच्छी आय अर्जित की है। किसान भाईयों में पशुपालन को लेकर रूचि बढ़ी है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीते कई महीनों से देखा जा रहा है कि गोबर खरीदी में भुगतान की जाने वाली राशि में से 60 से 70 प्रतिशत राशि गौठान समितियों द्वारा स्वयं की जमा पूंजी से की जा रही है। यह गौठान समितियों की सक्रियता और उनकी मेहनत का फल है। गौठानों में अभी भी 4.83 लाख क्विंटल वर्मी कम्पोस्ट उपलब्ध है। मैं सभी किसान भाईयों से अपील करता हूं कि वे खेतों में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का इस्तेमाल करें।

कार्यक्रम में कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि करीब 38 लाख हेक्टेयर में बोनी का कार्य हो गया है। खेतों में बियासी और रोपाई का कार्य चल रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी किसान अच्छा उत्पादन करेंगे। छत्तीसगढ़ में किसान शासकीय योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है।

उल्लेखनीय है कि गौठानों में गोबर खरीदी में स्वावलंबी गोठानों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। गोबर विक्रेताओं को होने वाले 5.60 करोड़ रूपए के भुगतान में से मात्र 2.29 करोड़ रूपए का भुगतान शासन की ओर से किया गया। जबकि 3.31 करोड़ रूपए का भुगतान स्वावलंबी गौठान स्वयं की राशि से किया। राज्य में 10,278 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं, जिसमें से 5985 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठानों ने अब तक 70.27 करोड़ रूपए का गोबर पशुपालक किसानों से स्वयं की राशि से किया है।

गौरतलब है कि आज किसानों को राशि अंतरित करने के बाद गोधन न्याय योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 541.66 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गोधन न्याय योजना के तहत गौठानों में अब 128.34 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है, जिसमें से 125.54 लाख क्विंटल गोबर खरीदी की एवज में गोबर विक्रेताओं को 250.08 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 5.60 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद गोबर खरीदी के एवज में अब तक राशि 255.68 करोड़ रूपए का भुगतान किया जा चुका है। गौठानों समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 257.29 करोड़ रूपए के भुगतान किया जा चुका है। आज 9.69 करोड़ रूपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढक़र 266.98 करोड़ रूपए हो गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रबंध संचालक गोधन न्याय मिशन डॉ. अयाज फकीर भाई तम्बोली, राज्य नोडल अधिकारी रीपा गौरव सिंह, संचालक कृषि एवं पशुधन चंदन त्रिपाठी, उप सचिव तूलिका प्रजापति, संचालक उद्यानिकी मातेश्वरन, राज्य नोडल अधिकारी एनआरएलएम पद्मिनी भोई साहू एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480